SHRI D. N. TIWARY : May I know what is the criteria of a high quality a film or a film with intrinsic qualifications because the applicants who go for finance are harrassed on this norm ? Can you tell me what criteria has been laid down and what steps are taken to see that people are not harrassed ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : I do not agree with the hon. Member that the people are being harassed by the Film Finance Corporation. As I have already mentioned, the resources of the Film Finance Corporation are limited. It is not possible to meet the demand of all people who apply for finance. To decide about the artistic merit of the film, there is an expert committee and there are a number of committees which go through the script the treatment and other things of the film. They examine the whole thing and then decide it.

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी सूची है कि वित्त के बिना या जिन साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे रा-मैटीरियल, उन के बिना कितने चित्र अभी अधूरे पड़े हैं ?

MR. SPEAKER : It need not be answered because that is not a relevant question.

SHRI G. VISWANATHAN : In view of the shortage of films in the country and in view of the import of raw films from foreign countries involving foreign exchange, may I know from the hon. Minister whether the capacity of the Hindustan Photo films will be increased so that we become self-sufficient in raw films and may I know when we will achieve self-sufficiency ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : It is not the question of increasing the capacity of Hindustan Photo Films. Actually, these are temporary shortages in production and they are trying to meet the shortages. They are also trying to improve the quality of films.

SHRI AMRIT NAHATA : The production of black and white films in our country has gone down considerably. About 85 per cent of films that are produced in the country are colour films. We do not manufacture raw colour films in our country and immense foreign exchange is being spent over the import of raw colour films. The quality of positive black and white films that are produced in our country is good but the black and white negative is of low quality. Will the Government consider improving the quality of black and white negative in our country and also will the Government consider setting up of a plant for the manufacture of colour films.

MR. SPEAKER : The question is about financing.

SHRI N. K. SANGHI : There is no doubt that there is a very serious crisis in the film industry. More than 300 films are lying on the shelf for want of finance and raw materials. The hon. Minister just now said that the Film Finance Corporation is not in a position to give adequate finance for the production of films. May I know from the hon. Minister whether she will move the Government to recognise film industry as an industry and also move the Government to give financial aid to the film industry so that they can also survive and feel that they are a part of the country and they get out of the crisis. The Hindustan Photo Films has been closed for more than six months. That is the reason why raw material is not available in the country. I would like to know what steps Government are taking in the matter.

MR. SPEAKER : It is not a question but a suggestion.

अखबारी कागज के आयात के बारे में भारत-रूस करार

*676. श्री राजावतार शास्त्री : क्या विदेश-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से रूस के साथ अखबारी कागज के आयात के सम्बन्ध में करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल०एन०मिश्र): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारतीय राज्य व्यापार निगम ने सोवियत संघ से 40,000 मी० टन अखबारी कागज का भारत में आयात करने के लिये 21 मई, 1971 को मैसर्स एक्सपोर्टल्स, मास्को के साथ एक संविदा की है। माल की सुपुर्दगी जुलाई, 1971 से अप्रैल, 1972 तक की अवधि के दौरान की जाएगी।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ 40 हजार टन अखबारी कागज मंगाने का जो समझौता हुआ है क्या इसके पीछे कोई शर्त भी है, यदि है तो उन शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस तरह की संधियों में जो शर्तें होती हैं, वे इस में भी हैं, जैसे रुपयों में पेमेंट होगा। 1971-72 का जो समझौता व्यापार के बारे में रूस के साथ हुआ है, यह समझौता उसी का एक अंग है। इस किस्म के समझौतों में जो शर्तें होती है, वे ही इस में हैं—डैफर्ड पेमेंट होगा, धीरे-धीरे कीमत देनी है, उसके बदले में माल लेना है। माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि दिसम्बर, 1970 में हमने वह करारनामा सभा-पटल पर रखा था।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या सोवियत संघ के अलावा भी कुछ मुल्कों से अखबारी कागज का आयात करते हैं ? अगर करते हैं तो कितना और उन मुल्कों के नाम क्या हैं ? क्या विभिन्न मुल्कों की कीमतों में कोई फर्क हैं ? अगर फर्क है तो उस का ब्यौरा क्या है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मुल्क तो बहुत से हैं—जैसे कैनाडा, जैकोस्लावेकिया, फिनलेंड, वैस्ट जर्मनी, नार्वे, पोलेंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यू०एस०ए० और यू०एस०एस०आर०—हम इन मुल्कों से अखबारी कागज मंगाते हैं। जहां तक रूस का सवाल है—जितना माल हम मंगाते हैं उसका 31 प्रतिशत रूस से मंगाते हैं। कीमतों के बारे में यहां बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न देशों से विभिन्न कीमतों पर मंगाते हैं और उनका बताना देश के हित में नहीं होगा।

SHRI S. M. BANERJEE : I would like to know whether one of the conditions of the import of newspint from the Soviet Union is that this newsprint will not go to those who preach communalism or provincialism in their newspapers. Is this one of the conditions ?

SHRI L. N. MISHRA : There are no such conditions and we will not accept any such conditions in any trade agreement.

श्री फूल चन्द्र वर्मा : रूस से जो अखबारी कागज हम मंगाते हैं—क्या यह सत्य नहीं है की अन्य देशों से जो अखबारी कागज आता है, उनकी कीमत से रूस की कीमत अधिक है, उस के बावजूद भी हम उनसे खरीदते हैं ?

क्या यह सत्य नहीं है कि जो अखबारी कागज हमारे यहां आता है, वह ऐसे अखबारों या समाचार-पत्रों को दिया जाता है, जो देश विरोधी प्रचार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं को अधिक कागज दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो समझौते के बारे में था।

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक कीमत की बात है में पहले बता चुका हूँ कि किस देश से किस कीमत पर लिया जाता है, यह बताना देश के हित में नहीं है, इससे हमारी नेगोशियेटिंग कैपेसिटी पर असर पड़ेगा। जहां तक अखबारों को कागज देने का सवाल है, सब कागजों को पूल कर दिया जाता है और फिर इन्फर्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री उस का बटवारा करती है। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि किस देश का कागज किस अखबार को जाना चाहिये।